भारत और अमरीका के लिए पाकिस्तानी चुनौती
The Pakistan Challenge for India and America

ब्रूस राइडल
Bruce Riedel
November 5, 2012

भले ही भागीदार के रूप में अमरीका और भारत के रिश्ते कितने ही गहरे होते जा रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की चुनौतियों से वे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते. सन् 1947 से ही वाशिंगटन और नई दिल्ली के द्विपक्षीय संबंधों में यही सबसे बड़ी अड़चन रही है. अमरीका के अगले राष्ट्रपति और भारत के अगले प्रधानमंत्री अब पाकिस्तानी खतरों और अवसरों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे. वाशिंगटन और नई दिल्ली के सहयोग के लिए इन चुनौतियों से जूझना बहुत ज़रूरी होगा और सौभाग्य से अफ़गानिस्तान में विशेष रूप से 2014 के संक्रमण के लिए तैयारी की प्रक्रिया में यह सहयोग बढ़ता हुआ दिखायी दे रहा है.

भारत और अमरीका दोनों के ही संबंध पाकिस्तान से बिगड़े हुए और जटिल रहे हैं. 26 नवंबर, 2008 को मुंबई पर आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान और भारत के संबंधों में और भी अधिक दरार आ गयी है. सौभाग्य से खास तौर पर नई दिल्ली ने संयम से काम लिया और चार साल के बाद धीरे-धीरे दोनों देशों के संबंध सुधरने लगे हैं. दोनों देशों के बीच यात्रियों के लिए वीज़ा के प्रतिबंध कम होने लगे हैं और वास्तविक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर वार्ता चल रही है. इन उपायों से दोनों देशों को लाभ होगा, विशेषकर पाकिस्तान को जिसकी अर्थव्यवस्था लचर है. राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने भारत का दौरा किया है और लगता है कि वे सचमुच ही संबंधों में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. सितंबर के चुनावी सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के अंतर्विरोध को बखूबी समझता है. यद्यपि 77 प्रतिशत भारतीय लोग पाकिस्तान को अपना शत्रुदेश मानते हैं, फिर भी 77 प्रतिशत भारतीय यह भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए कश्मीर के विवाद को सुलझाना बेहद ज़रूरी है.

लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफ़िया एजेंसी आईएसआई संबंधों को सुधारने के लिए कितनी प्रतिबद्ध हैं. परंपरागत रूप में वे भारत को शत्रुदेश के रूप में ही देखते आये हैं और उनके राष्ट्रीय बजट की असंगति का कारण भी यही है. पाकिस्तान के लुटेरों के साथ उनके लश्करे तायिबा के सरगना मुहम्मद हफ़ीज़ सईद को पकड़वाने के लिए सूचना देने वाले को अमरीका ने इनाम देने की घोषणा कर दी है, लेकिन वह पाकिस्तान में खुले-आम अपना ऑपरेशन चला रहा है. मुंबई हत्याकांड का मुखिया देश-भर में घूमता है, आईएसआई के संरक्षण में आयोजित रैलियों में खुले-आम भाग लेता है और नियमित रूप में वार्ताओं में भाग लेता है और भारत व अमरीका के खिलाफ़ ज़ेहाद छेड़ने की माँग करता है. बड़े पैमाने पर अगले हमले की पूरी आशंका है और विडंबना तो यही है कि यदि शांति-वार्ताएँ आगे बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के आतंकी दल इन वार्ताओं को विफल करने के लिए भी कमर कसे बैठे हैं.

इसी साल सउदी अरब से अबू जिंदल के छद्मनाम वाले एलईटी के सरगने का (अमरीकी मदद से) भारत में प्रत्यर्पण इसी खतरे को ही दर्शाता है. वह जब भारत पर एक और बड़े हमले के लिए सउदी अरब में पैसा जुटा रहा था तो उसे गिरफ़्तार करके भारत भेज दिया गया. उसकी आवाज़ एलईटी के उसी मुखिया से मेल खाती है जिसने मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादियों को फ़ोन पर बंधकों को मारने के आदेश दिये थे, जिसे भारतीय सुरक्षा सेवाओं ने मॉनिटर कर लिया था.

पाकिस्तान के साथ तो अमरीका के संबंध और भी अधिक जटिल हैं और निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं. एक ओर अमरीका इस सदी में पाकिस्तान के प्रति बहुत उदार रहा है. 9/11 से अमरीका ने इस्लामाबाद को $25 बिलियन डॉलर की सैनिक और आर्थिक मदद दी है. सैनिक मदद में अठारह जैट युद्धक विमान, पाँच सौ ऐमराम हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, छह सी-130 परिवहन विमान, बीस कोबरा हमलावर हैलिकॉप्टर और पैरी क्लास युद्धपोत शामिल रहे हैं. कांग्रेस अनुसंधान सेवा के अनुसार लगभग आधी मदद तो जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति-काल में ही दे दी गयी थी और शेष आधी मदद बराक ओबामा के राष्ट्रपति-काल में दी गयी. सन् 2001 से लेकर अब तक इज़रायल के अलावा किसी भी देश को इतनी अमरीकी मदद नहीं मिली है.

दूसरी ओर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के विरोधी हैं. अनेक रूपों में अमरीका अफ़गानिस्तान में छद्म युद्ध लड़ रहा है. अमरीका, नैटो और चालीस से अधिक देशों के सैनिक हामिद करज़ई के नेतृत्व में कानूनी तौर पर चुनी गयी काबुल सरकार का समर्थन कर रहे हैं और भारत भी उनमें से एक है. पाकिस्तान मुँह से तो करज़ई सरकार का समर्थन करता है, लेकिन उनके शत्रु अफ़गानी तालिबान की मुख्य रूप से सहायता करता है. आईएसआई क्वेटा, कराची और वज़ीरिस्तान में तालिबानी नेतृत्व को शरण देता है, उनके योद्धाओं को प्रशिक्षित करता है और अफ़गानी सरकार और नैटो के ठिकानों पर हमला करने में उनकी मदद करता है. हज़ारों की संख्या में पकड़े गये तालिबानी योद्धाओं की तफ़तीश से पता चला है कि विद्रोहियों की कामयाबी के पीछे पाकिस्तान का हाथ रहा है. वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि विद्रोही आईएसआई से सीधे निर्देश लेते हैं.

पाकिस्तानी संसद और विदेश मंत्रालय ने अमरीका से स्पष्ट रूप में पाकिस्तानी सीमा के अंदर उड़ान न भरने के लिए अनुरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद अमरीका अल कायदा और संबंधित दलों के आतंकी ठिकानों पर ड्रोन से हमला भी कर रहा है. हर रोज़ ही अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी सीमा के अंदर संभावित ठिकानों की टोह लेते हैं. सन् 2004 से लेकर 30 सितंबर, 2012 तक ड्रोन ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर 346 घातक हमले किये. इनमें से लगभग 300 हमले ओबामा की निगरानी में किये गये. ड्रोन के हमलों ने अल कायदा के नेतृत्व को नेस्तनाबूद कर दिया है और साथ ही पाकिस्तानियों को भी नाराज़ कर दिया है और लोग अमरीका-विरोधी रैलियाँ निकाल रहे हैं. इनमें लश्करे तायिबा और इमरान खान सहित पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं.

अंततः अबोटाबाद की छाया अमरीकी-पाकिस्तानी संबंधों पर मँडरा रही है. यह कैसे संभव हुआ कि सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की प्रमुख सैन्य अकादमी से केवल आठ गज़ की दूरी पर पाँच साल से अधिक समय तक छिपा रहा? एक पाकिस्तानी अधिकारी ने इसे मात्र संयोग माना है, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? अमरीका की स्थल, वायु और जल सेना की संयुक्त कमान 'सील' के हमले में अल कायदा के अमीर को मार देने के बाद एक पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा था कि "निश्चय ही जनरल जानते थे और यह भी जानते थे कि वे इसके दोषारोपण से भी बच सकते हैं." या तो यह आईएसआई की अकर्मण्यता थी या फिर उनकी मिलीभगत. दोनों ही बातें बेचैन करने वाली हैं.

सन् 2014 में अफ़गानिस्तान में युद्ध की कमान नैटो के हाथों से लेकर अफ़गानी नेतृत्व को सौंपने के आगामी संक्रमण की प्रक्रिया अमरीकी-पाकिस्तानी संबंधों की अग्निपरीक्षा होगी और इसमें भारत के लिए भी कई महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे. यदि पाकिस्तान काबुल सरकार पर दबाव बनाने के लिए तालिबान को प्रोत्साहित करता है और वे हेलमंद और कंधार में नैटो सैन्यबल द्वारा बहुत कठिनाई से जीती गयी ज़मीन हथिया लेते हैं तो यह साफ़ हो जाएगा कि पाकिस्तान अमरीका को दक्षिण एशिया से खदेड़ने के लिए कृतसंकल्प है. बहुत-से अमरीकी लोग अफ़गानिस्तान में किसी भी अमरीकी पराजय के लिए पाकिस्तान को ही दोषी ठहराएँगे और यह सिद्ध करने के लिए उनके पास उचित कारण भी होंगे.

लगता है कि भारत को भी अफ़गानी संघर्ष में घसीटा जा सकता है. भारत पहले से ही काबुल का प्रबल समर्थक है और इसने सन् 2001 से लेकर अब तक काबुल को $2 बिलियन डॉलर की सहायता दी है और यह भी संभव है कि भारत तालिबान-विरोधी उत्तरी संधि का प्रमुख क्षेत्रीय मित्रदेश बन जाए. अमरीकी-पाकिस्तानी छद्म युद्ध भारत-पाकिस्तानी छद्म युद्ध बन सकता है.

इसका बेहतर विकल्प भी हैः पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर निश्चित तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है ताकि तालिबान काबुल में चल रही गंभीर राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सके और इस प्रकार अल कायदा को उससे अलग किया जा सके. इस विकल्प से अफ़गानिस्तान में चल रहा तीस साल पुराना युद्ध क्षेत्रीय संधि द्वारा समर्थित समझौते के ज़रिये किये गये करार के आधार पर खत्म किया जा सकता है. विकल्प पाकिस्तान के हाथ में है. यदि पाकिस्तान यह विकल्प नहीं अपनाता है तो अमरीका और भारत को साथ मिलकर काम करना होगा और यह सोचना होगा कि पाकिस्तान और उसकी सेना की ज़्यादतियों से कैसे निपटा जाए. सौभाग्यवश, दोनों ही देश अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर पहले से ही मिलकर काम कर रहे हैं. भारत-अमरीका के रणनीतिक संवाद के पिछले सत्र में अफ़गानिस्तान के भविष्य को लेकर काफ़ी लंबे समय तक विचार-विमर्श किया गया. दोनों के संयुक्त बयान से यही संकेत मिलता है. यह सही दिशा में उठाया गया कदम है.

ब्रूस राइडल ब्रुकिंग्स संस्था में वरिष्ठ फ़ैलो हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, 1997-2001 *के पूर्व और दक्षिण एशिया के नज़दीकी मामलों के पूर्व वरिष्ठ निदेशक रहे हैं. वे 'कैसी' के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं.*

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>